

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

‘ कि यह सभा संसद् सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के लिये मार्ग-दर्शन के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र, 1972 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ती है ।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वक्तव्य

Statement re. Prime Minister's Visit abroad

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं हाल ही में बेल्जियम, आस्ट्रिया, ब्रिटेन, अमरीका फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी की यात्रा से लौटी हूँ। बंगला देश में और पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर गम्भीर स्थिति के बावजूद मैंने यह यात्रा इस लिए की क्योंकि यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम पर जो बोझ डाला गया है उसे कम करने और साथ ही उन लोगों को हतोत्साहित करने, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के बहाने ढूँढ रहे हैं, हर सम्भव उपाय किए जायें। मुझे जनता के मनोबल तथा सब दलों की एकता पर पूरा भरोसा था। इसी लिए मैं इस समय, जब राष्ट्र को खतरा है, इस यात्रा को कर पाई हूँ। इस यात्रा में मुझे विभिन्न देशों की सरकारों के अध्यक्षों तथा जनता के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने तथा उनके समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों, आपसी सम्बन्धों, विशेषकर बंगला देश की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचे तथा इस क्षेत्र में शान्ति को पैदा हुए खतरे के बारे में अपना मत पेश करने का अवसर मिला है। बातचीत के परिणामस्वरूप कई गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। समस्या का मूल कारण यह है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपनी ही जनता के निर्णय को अस्वीकार किया है और बंगला देश में भारी आतंक फैलाया है जिसके बाद भारी संख्या में शरणार्थी भारत आये हैं। मेरे विचार से अब ये देश तथा अन्य देश महसूस करते हैं कि जब तक इस समस्या का पूर्वी बंगाल की जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के साथ बातचीत करके उनकी वास्तविक इच्छाओं के अनुसार कोई राजनीतिक हल नहीं निकाला जाता, अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अधिकाँश देश इस बात को भी महसूस करते हैं कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करना अत्यन्त आवश्यक है और इस परियोजन के लिए पाकिस्तानी शासकों पर दबाव डाला जाना चाहिये। अब तक इस मामले को पाकिस्तान का आंतरिक मामला समझा जाता था परन्तु अब इस समस्या का तुरन्त समाधान करने की भावना बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की मूल विषय को अलग करने और संयुक्त राष्ट्र को बीच में लाकर इस तनावपूर्ण स्थिति को भारत-पाकिस्तान संघर्ष का रूप देने की

कोशिश असफल रही है। अब भारत पाकिस्तान की चालों से गुमराह नहीं होगा और पाकिस्तानी सैनिक जनता को उन लोगों के साथ, जिनके साथ उन्होंने अन्याय और बर्बरता से व्यवहार किया है, समझौता कर लेना चाहिए।

अमरीका की यात्रा के दौरान मुझे बताया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान को और सैनिक सामान भेजना बन्द कर दिया है। इस बीच इस बारे में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुझे यह भी बताया गया था कि ब्रिटेन, फ्रांस, और जर्मन रिपब्लिक से भी हथियार सप्लाई नहीं किये जा रहे हैं। पाकिस्तान को यह महसूस करना चाहिए कि भारत पर सैनिक कार्यवाही करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आशा है कि जिन नेताओं से मैं मिली हूँ, वे इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे क्योंकि ठोस तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम जिस प्रकार 90 लाख शरणार्थियों की देखभाल कर रहे हैं। उसके बारे में सभी देशों की सहानुभूति हमारे साथ है।

ये सब देश इस पर इस बात पर सहमत हैं कि पूर्वी बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे शरणार्थियों की संख्या और न बढ़े और भारत में आए शरणार्थी भी सुरक्षा की भावना और मानवीय प्रतिष्ठा के साथ अपने देश लौट सकें।

इसके साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमारी सुरक्षा का सम्बन्ध है, हमें अपनी स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करने के लिये तैयार रहना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब तक बंगला देश की स्थिति का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, जिससे कि हमारे देश को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, हम सीमाओं से अपनी सेनाओं को हटाकर खतरा मौल नहीं ले सकते। इस समय योरुप में समझौते की भावना है और हमें आशा है कि इस महाद्वीप में स्थाई सुरक्षा का कोई उपाय निकल आयेगा। इसका प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर भी पड़ेगा।

उपर्युक्त देशों के साथ आपसी आर्थिक सम्बन्धों पर भी चर्चा की गई थी। बेल्जियम, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी ने महसूस किया है कि भारत और योरुपीय आर्थिक समुदाय के बीच सम्बन्धों के सुधार के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। औद्योगिक, प्राद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हमारे सहयोग की नई सम्भावनाएँ पैदा हुई हैं।

मेरे विचार में इस यात्रा से ब्रिटेन के हमारे सम्बन्धों को, जिन्हें वर्ष 1965 में भारी धक्का लगा था, पुनः सुधारने में भी सहायता मिली है। अन्त में अपनी जनता और राजनीतिक दलों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बड़ी बुद्धिमता और संयंत्र से काम लिया है और विदेशी खतरे का सामना करने के लिये एकता बनाये रखी है।